

बोझ के बजाय सुगमता बढ़ाएं कानून

मैट्रोलोजी कानून यानी 'विधिक माप-विज्ञान' अधिनियम' का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सामान का वजन और माप सही हो। यह कानून सुनिश्चित करता है कि जब आप कुछ खरीदते हैं तो आपको उतनी ही मात्रा या माप की वस्तु मिले, जितनी पैकेट पर लिखी हुई है। प्री-पैकड वस्तुओं की लेबलिंग के मामले भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रोडक्ट का नाम, वजन और निर्माता की जानकारी आदि। इस कानून के तहत ऐसे व्यवसाय, जो वजन और माप संबंधी उपकरण बनाते, बेचते, आयात या मरम्मत करते हैं, उन्हें लाइसेंस प्राप्त करना भी अनिवार्य है। भले ही किसी व्यवसाय का गलत इरादा न हो, पर यह कानून व्यवसायों पर बड़ा बोझ डालता है। हमने इस संदर्भ में कुछ चुनौतियों और उनके समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पहला, हमारी मौजूदा लेबलिंग आवश्यकताएं अत्यंत जटिल हैं।



दि ग्राज फैशन ब्रांड एचरेंडरम को 2016 में एक स्टेटर का माप 1.22 मीटर के बजाय 122 सेटीमीटर बताना महंगा पढ़ गया। इस कारण उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। इसी तरह ब्रिटानिया पर भी मैट्रोलोजी कानून यानी माप से जुड़े कानून के तहत एक थोक बाक्स पर 120 एन या 120 यू के बजाय '120 पैक्स' लिखने के लिए मुकदमा चलाया गया।

लेबलिंग नियमों के उल्लंघन पर आइटीसी को मध्य प्रदेश में छ हाल तक कानूनी लडाई लड़नी पड़ी, क्योंकि उसने अरहर दाल के पैकेट पर एक साधारण वाक्यांश 'जब पैक किया गया' लिख दिया, जो तय नियमों में नहीं आता था। ये कुछ भिसाले हैं, जो मैट्रोलोजी कानूनों की जटिलताओं के चलते कानून व्यवस्था पर पड़ने वाले अनावश्यक बोझ को दर्शाती हैं। इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2021-22 में ही अप्रमाणित वजन और माप की वजह से 35,840 मामले दर्ज किए गए।

मैट्रोलोजी कानून यानी 'विधिक माप-विज्ञान अधिनियम' का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सामान का वजन और माप सही हो। यह कानून सुनिश्चित करता है कि जब आप कुछ खरीदते हैं तो आपको उतनी ही मात्रा या माप की वस्तु मिले, जितनी पैकेट पर लिखी हुई है। पी-पैकड वस्तुओं की लेबलिंग के मामले भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रोडक्ट का नाम, वजन और निर्माता की जानकारी आदि। इस कानून के तहत ऐसे व्यवसाय, जो वजन और माप संबंधी उपकरण बनाते, बेचते, आयात या मरम्मत करते हैं, उन्हें लाइसेंस प्राप्त करना भी अनिवार्य है। भले ही किसी व्यवसाय का गलत झड़ादा न हो, पर यह

कानून व्यवसायों पर बड़ा बोझ डालता है। हमने इस संदर्भ में कुछ चुनौतियों और उनके समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

पहला, हमारी मौजूदा लेबलिंग आवश्यकताएं अत्यंत जटिल हैं और मौजूदा नियमों में बहुत ही सूक्ष्म निर्देश दिए गए हैं। उदाहरण के रूप में अकें की माप, शब्दों की ऊँचाई और चौड़ाई और लेबल का आकार आदि। हमें अंक, शब्दों की माप, पैकेजिंग कवर के प्रतिशत आदि से संबंधित निर्धारित आवश्यकताओं से हटकर व्यावहारिक मापदंडों का उपयोग करना चाहिए। जैसे लेबल स्पष्ट रूप से चिह्नित हो, प्रमुखता से दिखाई दे और आसानी से पढ़ा जा सके और यदि विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है तो उसे किंक-रिस्पास यानी क्यूआर कोड से जोड़ा जा सकता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और दवाओं में ऐसा किया भी जाता है, ताकि ग्राहक सही जानकारी हासिल कर सकें। दूसरा, जिन उत्पादों के लिए आम तौर पर मीट्रिक प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां अन्य उपयोग स्वीकार किए जाने चाहिए। ऐसा न करने से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जैसे लैपटाप और मोबाइल के लिए कानून के अनुसार सेंटीमीटर में माप दी जानी चाहिए, लैकिन इसके लिए चलन इंच में माप देने का है। ऐसे में यदि किसी उत्पाद को सामान्यतः गैर-मीट्रिक इकाइयों में मापा जाता है, तो उनके उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। वर्तमान में, लीगल मेट्रोलाजी एक्ट के तहत दर्ज किए गए कुल उल्लंघनों में लगभग 10 प्रतिशत मामले गैर-मानक इकाइयों के उपयोग से जुड़े हैं, जो कानून व्यवस्था पर बोझ डालने का काम करते हैं। तीसरा, इस अधिनियम में कई उल्लंघनों के लिए अभी भी आपाराधिक दंड का प्रविधान है। इससे

अधिकारियों को अनुचित लाभ के लिए दबाव बनाने का मौका मिलता है और व्यवसायों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसलिए अधिनियम के किसी भी उल्लंघन को आपाराधिक श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए। हालांकि जन विश्वास अधिनियम ने दंड के दायरे को सीमित किया है, फिर भी मामूली आपाराधिक लिए एक साल तक की सजा का प्रविधान अब भी मौजूद है। जबकि इसके बजाय केवल सुधारात्मक आदेश और आर्थिक दंड लगाया जाए।

चौथा, फिलहाल कंपनियों को वजन और माप के लिए एक अलग लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है जो पहले से ही मौजूद जटिल प्रक्रियाओं को और बोझिल बनाते हैं। हर राज्य के अपने नियम-कानून हैं और ऐसे उपकरणों के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है, जिन्हें पहले से अनिवार्य बीआइएस प्रमाण मिला हुआ है। जो निर्माता पहले से ही दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, जीएसटी और अन्य कानूनों के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें भी एक अलग 'पैकर/निर्माता' के रूप में पंजीकरण करना पड़ता है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए यह प्रक्रिया लागत और समय दोनों बढ़ाती है। यह सही नहीं है। हमें इस प्रक्रिया को सरल बनाने और इसे अन्य मौजूदा लाइसेंसों के साथ जोड़ने पर काम करना चाहिए ताकि समय और पैसे दोनों की बचत हो सके। हमारी मंशा इस कानून को रद करने की नहीं, बल्कि उसे सरल-हडज और व्यवसायों के और अनुकूल बनाने की है। बाजार में लेन-देन और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा जरूरी है, लैकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि नियम, कानून और परिमित किस हद तक सही हैं और ये व्यवसायों के लिए प्रेरणानी न बनें।

अंतरिक्ष तक पहुंचने वाले देश में ही हैं रुढ़िवादी लोग



अंतरिक्ष में पांव रख चुके भारत में आज भी कई तरह की रूढ़ियां आम दिखती हैं, तो इसकी वजह यही है कि हम कई मामलों में मानसिक रूप से दशकों पीछे जी रहे हैं। अन्यथा एक प्रगतिशील समाज में और वह भी स्कूल जैसी जगह पर माहवारी की जांच के नाम पर स्कूली छात्राओं के कपड़े नहीं उतरवाए जाते। इससे अधिक अफसोसनाक बात क्या हो सकती है कि ठाणे जिले के जिस विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों को भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाया गया, वहां प्रधानाचार्य खुद एक महिला हैं। परिसर में उनके रहते यह सब हुआ। विचित्र यह है कि शौचालय में फर्श पर खून के धब्बे होने की जानकारी के बाद जहां प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षिकाओं को बेहद संवेदनशील तरीके से पेश आने की जरूरत थी, वहां बच्चियों को न केवल स्कूल सभागार में बुलाया गया, बल्कि सार्वजनिक रूप से उनसे यह पूछा गया कि क्या उनमें से कोई मासिक धर्म चक्र से गुजर रही है। जिन छात्राओं ने इनकार किया, उनकी अभद्र तरीके से जांच की गई। निस्संदेह बच्चियों से यह व्यवहार अक्षम्य है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने उचित कार्रवाई की और इस मामले में प्रधानाचार्य सहित एक महिला कर्मी को गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि महिलाओं के जिस प्राकृतिक चक्र या अवस्था को समझने-जानने और बच्चियों को उचित तरीके से शिक्षित करने की जरूरत है, वहां स्कूल जैसी जगह में भी उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, जिससे इस अवस्था के प्रति कम उम्र की लड़कियों के भीतर नाहक आशंका पैदा होती है। ठाणे के स्कूल में माहवारी की जांच के नाम पर जिन बच्चियों के साथ अवांछित हरकत की गई, उनके मन-मस्तिष्क पर इसके असर का अंदाजा लगाया जा सकता है। पारंपरिक जड़ता के घेरे में घरों-परिवारों में महावारी के दौरान लड़कियों के प्रति कई तरह के दुराग्रह पहले ही मौजूद रहे हैं।

मतदाता सूची के सत्यापन पर व्यर्थ का शोर



बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के पहले चुनाव आयोग ने राज्य में मतदाता सूची के सत्यापन अर्थात् पुनरीक्षण की जो पहल की, उस पर कांग्रेस, राजद समेत अनेक विपक्षी दलों ने आसमान सिर पर उठा लिया। इन दलों ने यह बताने की कोशिश की कि चुनाव आयोग कोई अनुचित, अनावश्यक और असर्वैधानिक काम कर रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मोदी सरकार पर भी तमाम आरोप लगाए। उनके हिसाब से चुनाव आयोग मतदाता सूची का सत्यापन मोदी सरकार के कहने पर कर रहा है और उसका इतावा किसी न किसी प्रकार भाजपा को चुनावी लाभ पहुंचाना है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की इस पहल को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हुई तथाकथित हराफें से भी जोड़ा। वह बार-बार यह घिसा-पिटा आरोप दोहरा रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए धार्थीली करवाई। इन आरोपों का चुनाव आयोग ने विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन राहुल गांधी और उनके साथ कई विपक्षी नेता सच का समना करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। साफ है कि उनके साथ कांग्रेस यह समझने को तैयार नहीं किए उनकी राजनीतिक जगीर कमज़ोर हो रही है और इसके लिए वे चुनाव आयोग पर दोष मढ़कर कुछ हासित नहीं कर सकते। मतदाता सूची का सत्यापन कोई नई बात नहीं है। बिहार में ही इसके पहले 2003 में मतदाता सूची का सत्यापन हुआ था। अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी मतदाता बढ़े हैं। बिहार के लाखों लोग रोजगार के सिलसिले में बाहर जाते हैं और कुछ तो वहाँ जाते हैं। इस तथ्य की भी अनदेखी सकती कि बांग्लादेश से होने वाले से पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के साथ झारखण्ड और बिहार भी प्रभावी सूची के सत्यापन से न केवल वास्तविक मतदाताओं का पata इसकी भी जानकारी हो सकेगी बांग्लादेशी बिहार में मतदाता तो न आखिर जब वे बंगाल में बन सकते भी इसकी आशंका है। चुनाव उक्त किया है कि मतदाता सूची का सत्यापन चुनाव की बुनियादी शर्त है। यदि इसकी पड़ताल की जाती रहे मतदाता कौन हैं और वे कहाँ रहते हैं? शायद ऐसे ही जाकारण चुनाव आयोग की पहल वेब राजनीतिक दलों और लोगों ने दरवाजा खटखटाया, उन्हें निराश सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाने से इन्कार कर दिया। इतने उसने चुनाव आयोग को मतदाता के लिए आधार, राशन कार्ड, वोट इस्तेमाल करने का सुझाव दिया कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट अमल करने को तैयार है। सुप्रीम स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग नागरिकता तय करना नहीं है। आयोग का इस संर्द्ध में यह क

मतदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि नागरिकता तय करने का काम गृह मंत्रालय का है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। यह फैसला चुनाव आयोग की अनावश्यक आतोचना करने वालों को आईना दिखाने वाला है। उसने व्यर्थ की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने का ही काम किया। चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर सवाल पहल भी उठाए जाते रहे हैं। हाल के समय में सबसे ज्यादा सवाल ईवीएम पर उठे हैं। सवाल उठाने वाले दलों में कांग्रेस सबसे आगे है, जबकि उसके समय में ही ईवीएम पर अमल शुरू हुआ। केंद्र की सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस लगातार यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि भाजपा ईवीएम में कुछ डब्ड़ी कराकर चुनाव जीत रही है। वह और उसके सहयोगी राजनीतिक दल जब ऐसे आरोप लगाते हैं तो यह भूत जाते हैं कि वे भी तो चुनाव जीतते रहते हैं। उन्होंने झारखण्ड में चुनावी जीत हासिल की थी। कांग्रेस यह देखने के तौयार नहीं कि उसके और सहयोगी दलों के प्रत्याशी जितने अंतर से चुनाव हारते हैं, उतनी संख्या में अवैध वोट नहीं डलवाए जा सकते। कोई भी प्रक्रिया अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकती। चुनाव प्रक्रिया में भी कुछ कमियों या विसंगतियों का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन यह हर कोई मानेगा कि समय के साथ भारत की चुनाव प्रक्रिया में सुधार हुआ है और इसी कारण चुनाव आयोग की दुनिया भर में प्रतिष्ठा बढ़ी है।

बल्कि इनके अपराधों का शिकार होकर इनका जवाब देने, इन्हें बेनकाब करने के बजाय उल्टे शिशु मृग-सी आंखें चुरा कर हम स्त्रियां खुद ही छिपने लगती हैं। ऐसे मामले आम हैं जिनमें ऐसे घिनौने कृत्यों के बाद पीड़ित बच्ची को ही चुप रहने की हिदायत दी जाती है, यह कह कर कि बात खुली तो परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। कुंठा ऐसी कि झट से कह दिया जाता है कि लड़कियां शरीर दिखाने वाले कपड़े पहनती हैं तो निशाने पर आएंगी। लेकिन घरों में समूचे शारीरिक अंगों को ढकने के बाद भी,

मारे आसपास लोगों के मुँह से ऐसे 'आशीर्वचन' आता है कि 'जीते रहो, दूध-बताशे पीते रहो', 'दूधो नहाओ, पूतो फलो।' ऐसे 'आशीर्वचन' हम औरतें बुजुर्ज होकर भी कभी बेटी के फलने पूर्णने को लेकर फूटे मुँह से भी नहीं बोल पातीं। पिछले कई वर्षों से बलात्कार के मामलों को तेजी से बढ़ते देखा। छह महीने की उम्र से लेकर पांच साल या उससे भी कम उम्र की बचियों से बलात्कार और वर्वरता के चरम के रूह कण्ठ देने वाले व्यारे पढ़े-सुने। युवतियों के खिलाफ असामाजिक तत्त्वों के साथ-साथ नजदीकी रिश्तेदारों और यहां तक कि सौतेले बाप, भाई, प्रेमी तक के अपराध ने दिल दहला दिया। 'कस्सू' महज उत्तर स्त्री होना। नाबालिग या बालिग-सभी महिलाएं इस तरह की क्रूरता को झौल रही हैं। बहुत-से ऐसे भी मामले हैं जो गड़े पढ़े रह जाते हैं। बाप, भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार, ससुर, जेठ, देवर आदि से होने वाले शारीरिक शोषण के विस्तृद्ध उठी आवाज को अभी वह इज्जत नहीं मिली है, जो फिरी स्त्री के भीतर थोड़ी हिम्मत भरे। ऐसे मामले सामने आने पर आमतौर पर उसके मौखिक भयाक्रांत परिणाम सुना कर ही दब दिया जाता रहा है। हम ही जन्म देती हैं ऐसे लोगों को और ये हमें ही नहीं बख्खाते। मुझे लगता है कि कभी हममें है जो ऐसे लड़कों या पुरुषों की अपने ऊपर आपराधिक दृष्टि का आभास होते हुए भी समय पर इन्हें समाज के कठघरे में नहीं खड़ा करती। बल्कि इनके आपराधिक का शिकार होकर इनका जवाब देने, इन्हें बेनकाब करने के बजाय उल्टे शिशु मृग-सी आंखें चुरा कर हम स्त्रियां खुद ही छिपने लगती हैं। ऐसे मामले आम हैं जिनमें ऐसे घिनौने कृत्यों के बाद पीड़ित बच्ची जो ही चुप रहने की हिदायत दी जाती है, यह कह कर कि बात खुली तो परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। कुठुंगा ऐसी कि झट से कह दिया जाता है कि लड़कियां शरीर दिखाने वाले कपड़े पहनती हैं तो निशाने पर आएंगी। लेकिन घरों में समृद्ध शारीरिक अंगों को ढकने के बाद भी, पूरे भारतीय परिधान



वाली औरतें भी कहां नहीं पुरुषों की हवस का शिकार बनती हैं! खेत-खलिहानों, सरेआम बाजारों, अंधेरे बंद कमरों या कोठरियों में! पीछे मुड़ कर देखने से क्या लाभ! जो सबको याद है, वही बात करते हैं। न उसने छोटी स्कर्ट पहन रखी थी, न वह किसी पुरुष मित्र के साथ आधी रात को कहीं से आ रही थी, न वह बच्ची थी। वह किसी की बीवी थी, बहन थी, बेटी थी। वह कमज़ोर परिवार से थी, दलित थी। उसे जिस बर्बरता का शिकार होना पड़ा, वह कल्पना भी दहलाती है। हां, धानागाजी जैसी रोगटे खड़े कर देने वाली शर्मनाक घटना इसी दौर में घटी। सामूहिक बलात्कार, बर्बरता और असभ्यता का चरम। वीडियो बना कर बाद में भी शोषण-दमन। लानत है ऐसे मर्दों पर जो इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी-आपकी बुद्धिमत्ता फिर नई घटना पर सौचने लगेगी। दुखद, शर्मनाक, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए जैसे विचार जाहिर कर हम तब तक के लिए शांत हो जाएंगे, जब तक वैसा ही नया कुछ न घट जाए। सच क्या है? औरतें सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं देश में। सरेआम नौची जा रही हैं। समाज के अंधेरे बहरे लोगों को चौखे भी सुनाई नहीं देतीं। उनके चेहरे पर कहीं शर्म नहीं दिखती। वे कब और किन हालात में समझने और तकलीफ महसूस करने की कोशिश करेंगे! वक्त का पहिया कभी भी धूम सकता है। अपराध में डूबे ऐसे मनचलों की यौवन-वित्तिणा ने स्त्रियों का हमेशा ही शोषण कर उनकी जुबान पर ताला जड़ने का काम किया है। देवालयों से लेकर वेश्यालय तक इनकी बेशर्मी और औरतों की चीखों के ऐतिहासिक गवाह रहे हैं। धर्म की आँड़ में पनपता जिसमानी धौंथा मुँह में राम, बगल में छुरी जैसा दृश्य सामने करता है। कार्यस्थलों पर अधिकारियों से लेकर सहयोगियों तक का बातिव छिपा नहीं है। दूसरा पक्ष यह है कि गरीबों के लिए उनकी गरीबी एक जानलेवा समस्या है। अबोधों को उनके अनजानेपन की बजह से शिकार बना लिया जाता है। संबंधी अपनेपन का फायदा उठा कर लड़कियों को चुप करा देते हैं। समझदारी वाली युवतियों के खिलाफ जबरदस्ती। जाहिर है, मरना स्त्री को ही है। जिन 'कोठों' को समाज गंदा कहता है, 'नाइट बार' की कॉल गर्लर्स्, देह-व्यापार में धकेली गई युवतियां-ये सब स्त्रियां इस आपराधिक मर्द जाति की देन हैं। कानून और प्रशासन आपराधिक नींद में सोता है। नरीतंतन, ऐसे मामले धमने का नाम नहीं ले रहे।

